

ରାଜ୍ୟକାନ୍ତ

जालोर

Rashtradoot

जालोर, शुक्रवार 9 अगस्त, 2024

आज ही अपना सपना
साकार करें।
कोई भी इम्मीट सीरीज
एडीसन खरीदें @ ₹4.99L* में

आँफरा स्टॉक रहने तक



आधिक जानने के लिए

+10
ਅੰਤਰੀਜ਼



۲۷۰

ପ୍ରକାଶନ ଦ୍ୱାରା



દુનાફોટેનમેંસ સિસ્ટમ

+10
अन्य सेप्टी फीचर्स



ਕਾਵਯੋਗਿਤੀ ਸਿਰਦਾਸ

A close-up view of a car's front headrests, which are white and feature a small integrated display screen in the center.



ਰੇਵਸ ਪਾਕਿੰਗ ਕੇਮਰਾ

S.PRESSO *CELERIO* **ALTO** **K18**

E-BOOK TODAY AT WWW.MARITISI.COM OR VISIT YOUR NEAREST MARITISI DEALERSHIP.

MANDALGARH: CALL: 9602892417. **ASIND:** CALL: 9602892432. **BHARATPUR:** TM MOTORS: CALL: 05644-220970, 226392, 9251423393, 9251423395, 8094519222. **DHOLPUR:** CALL: 8094777002, 8094519222. **NAGAR:** CALL: 8094777876, 809400622. Terms and conditions apply. Offer valid for select models/ variants and in select states only. Accessories and features shown may not be part of standard equipment and may vary from variant to variant. Images used are for illustration purpose only. Appearance of black shade on glass is due to lighting effect. Maruti Suzuki reserves the right to withdraw the offers at any point in time without any advance notice.

विचार बिन्दु

अपने भाई बंधु जिसका आदर करते हैं, दूसरे भी उसका आदर करते हैं। -महाभारत

Justice Delayed is Justice Denied (न्याय में विलम्ब, न्याय नहीं मिलने के समान है)

सं

विधान लागू होने के बाद से न्याय व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आया है। सर्वोच्च न्यायालय को

आपराधिक पदकर चौकिए मता आपराधिक हो गया है और वह नामिक का मूल अधिकार ही साथ ही रोपय का कर्तव्य

है कि अन्याय सबको प्राप्त हो न्याय सत्ता, सुलभ व तरित हो। विलम्ब से दिया गया न्याय, यह नहीं मिलता जैसा

है। अन्याय 21 हमें विलम्ब के अधिकार देता है। तरित न्याय प्राप्त करना व्यक्तिका मूल अधिकार है।

देश के सभी न्यायालय में लाखों मुकदमें निर्णय की प्रतीक्षा में है। लोग न्याय की प्रतीक्षा में घुट-घुट कर मर रहे हैं। जेल भीड़ से भरे हैं न तो प्रतीक्षा न्यायालय है और न न्यायाधीश। न्यायालय व सकार विलम्ब के दोषी हैं, सुधार की कोई राह नहीं है।

सुधार कोटे में लगाया 50 Constitution Bench के केसेज सर्वोच्चिक विषयों के अनिम निर्णय की प्रतीक्षा में है, यह भी सच है। 1994 से अभी तक 2192 केसों का निस्तारण हो चुका है।

कानून है, ग्रीन ट्रिब्यूनल के अदेश के विलम्ब हाईकोर्ट में रिट याचिका नहीं होगी। हाईकोर्ट का अपाना ही

फैसला है कि रिट नहीं होगी, किन्तु मर्यादा का उल्लंघन कर वही हाईकोर्ट रिट याचिका में स्टैट देता है। कई

मामले इस विलम्ब के बाव सुधारों को मैं लिया हूँ, किन्तु निर्णय नहीं होता और अनियमितता के केस बढ़ रहे

है। अन्याय तरित न्याय की अवश्यकता है। सुधार कोटे की खण्डीपीठ ने क्रिमिनल अलैन ने, 812 में छत्तीसगढ़

इस खबर में पूरी प्रतियोगिता के लिया और दूर-दूरी

कर दिया। यह निमं विलम्ब है, क्योंकि

जिन तीन कुसियां को उसने जीता वह अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह सही है, किंतु यह भी सही है कि इसी विनेश

फॉरम ने 6 अगस्त 2004 को भारतीय कुसियां में अन्यायी अधियों में अंकित कराया था। विनेश ने 50

किलोग्राम कुसियां वर्ग में हल्ली बार भाग लेते हुए ग्राम और अपाराधी घर ही 7 PM

को आया। सुधार का प्राप्त करने के लिये यहीं जाए। जो Presumption कानून मानता है, अपाराधी उसे Rebut नहीं कर पाया

है। केस में PW 1 की शाहदत थी कि मुक्त की मृत्यु 5 PM को घर में हुई थी व अपाराधी घर ही 7 PM

को आया। सुधार का प्राप्त करने के लिये यहीं जाए। जो Presumption को Discharge करने के प्रसन ही

पैदा होता है। केस में दो बजे शाम को साथ-साथ थे। न्यायाधीश न्यायालय ने माना

न्यायालयों के पास समय नहीं है। जस्टिस ऑक्ने के निस्तारण में समय बर्बाद हो जाता है।

दिनांक 29 जुलाई 2024 के समाचार पर The Times of India के प्रथम पृष्ठ पर समाचार पढ़ा। यह समाचार द्वायल कोटे द्वारा जमानत देने के सम्बन्ध में या मानीय मुख्य न्यायाधीश ने अपने भाषण में कहा था कि Trial Judges Play Safe by Not Granting Bail मानीय मुख्य न्यायाधीश दी वाई चैट्सड ने कहा कि धोर-धोर सर्वोच्चिक मूर्यों का तथा व्यक्तिकी स्वतंत्रता (Liberty) का मूल्यांकन घटाता जा रहा है। सुधार कोटे में 5 सालों में केसकी की Pendency 35% बढ़ रही है। 62 लाख केसों से बढ़कर 46.8 लाख हो गये हैं। हाई कोर्ट्स में 2019 से 2023 तक यह Pendingency 4.6 लाख से 62 लाख तक है। नीचे की अदालतों में यह Pendingency 4.4 कोड है। कानून मंत्री में सोबत ने ये अदालतों से अंदर आया है। इसका अर्थ है कि न्यायालय के द्वायल कोटे की तरीकी से अपाराधी को प्रतास किया जाए। इसी विनेश फॉरम ने उसी दिन क्वार्टर्ट फॉरम एवं सेमीफाइनल में दो और मजबूत पाइलान में दो और मजबूत पहलवानों को हार्डेन में प्रवेश कर लिया था। इसी विनेश को इस खबर में अपाराधी को प्रतास किया जाए। इसी विनेश फॉरम ने उसी दिन क्वार्टर्ट फॉरम एवं सेमीफाइनल में एक घरी में कोई अपाराधी को ल्योगी पर सजा दी गई है। लोग न्याय की प्रतीक्षा में घुट-घुट कर मर रहे हैं। जेल भीड़ से भरे हैं न तो प्रतीक्षा न्यायालय है और न न्यायाधीश। न्यायालय व सकार विलम्ब के दोषी हैं, सुधार की कोई राह नहीं है।

कानून है, ग्रीन ट्रिब्यूनल के अदेश के विलम्ब हाईकोर्ट में रिट याचिका नहीं होगी। हाईकोर्ट का अपाना ही

फैसला है कि इस विलम्ब के बाव सुधारों को ल्योगी पर सजा दी जाए। जिन तीन कुसियां वर्ग में अन्यायी अधियों में अंकित कराया था। विनेश ने 50

किलोग्राम कुसियां वर्ग में हल्ली बार भाग लेते हुए ग्राम और अपाराधी घर ही 7 PM

को आया। सुधार का प्राप्त करने की प्रतीक्षा में यहीं जाए। जो Presumption को Discharge करने के प्रसन ही

पैदा होता है। केस में दो बजे शाम को साथ-साथ थे। न्यायाधीश न्यायालय ने माना

न्यायालयों के पास समय नहीं है। जस्टिस ऑक्ने के निस्तारण में समय बर्बाद हो जाता है।

दिनांक 29 जुलाई 2024 के समाचार पर The Times of India के प्रथम पृष्ठ पर समाचार पढ़ा। यह समाचार द्वायल कोटे द्वारा जमानत देने के सम्बन्ध में या मानीय मुख्य न्यायाधीश ने अपने भाषण में कहा था कि Trial Judges Play Safe by Not Granting Bail मानीय मुख्य न्यायाधीश दी वाई चैट्सड ने कहा कि धोर-धोर सर्वोच्चिक मूर्यों का तथा व्यक्तिकी स्वतंत्रता (Liberty) का मूल्यांकन घटाता जा रहा है। सुधार कोटे में 5 सालों में केसकी की Pendency 35% बढ़ रही है। 62 लाख केसों से बढ़कर 46.8 लाख हो गये हैं। हाई कोर्ट्स में 2019 से 2023 तक यह Pendingency 4.6 लाख से 62 लाख तक है। नीचे की अदालतों में यह Pendingency 4.4 कोड है। कानून मंत्री में सोबत ने ये अदालतों से अंदर आया है। इसका अर्थ है कि न्यायालय के द्वायल कोटे की तरीकी से अपाराधी को प्रतास किया जाए। इसी विनेश फॉरम ने उसी दिन क्वार्टर्ट फॉरम एवं सेमीफाइनल में एक घरी में कोई अपाराधी घर ही 7 PM को आया। सुधार का प्राप्त करने की प्रतीक्षा में यहीं जाए। जो Presumption को Discharge करने के प्रसन ही

पैदा होता है। केस में दो बजे शाम को साथ-साथ थे। न्यायाधीश न्यायालयों के पास समय नहीं है। जस्टिस ऑक्ने के निस्तारण में समय बर्बाद हो जाता है।

दिनांक 29 जुलाई 2024 के समाचार पर The Times of India के प्रथम पृष्ठ पर समाचार पढ़ा। यह समाचार द्वायल कोटे द्वारा जमानत देने के सम्बन्ध में या मानीय मुख्य न्यायाधीश ने अपने भाषण में कहा था कि Trial Judges Play Safe by Not Granting Bail मानीय मुख्य न्यायाधीश दी वाई चैट्सड ने कहा कि धोर-धोर सर्वोच्चिक मूर्यों का तथा व्यक्तिकी स्वतंत्रता (Liberty) का मूल्यांकन घटाता जा रहा है। सुधार कोटे में 5 सालों में केसकी की Pendency 35% बढ़ रही है। 62 लाख केसों से बढ़कर 46.8 लाख हो गये हैं। हाई कोर्ट्स में 2019 से 2023 तक यह Pendingency 4.6 लाख से 62 लाख तक है। नीचे की अदालतों में यह Pendingency 4.4 कोड है। कानून मंत्री में सोबत ने ये अदालतों से अंदर आया है। इसका अर्थ है कि न्यायालय के द्वायल कोटे की तरीकी से अपाराधी को प्रतास किया जाए। इसी विनेश फॉरम ने उसी दिन क्वार्टर्ट फॉरम एवं सेमीफाइनल में एक घरी में कोई अपाराधी घर ही 7 PM को आया। सुधार का प्राप्त करने की प्रतीक्षा में यहीं जाए। जो Presumption को Discharge करने के प्रसन ही

पैदा होता है। केस में दो बजे शाम को साथ-साथ थे। न्यायाधीश न्यायालयों के पास समय नहीं है। जस्टिस ऑक्ने के निस्तारण में समय बर्बाद हो जाता है।

दिनांक 29 जुलाई 2024 के समाचार पर The Times of India के प्रथम पृष्ठ पर समाचार पढ़ा। यह समाचार द्वायल कोटे द्वारा जमानत देने के सम्बन्ध में या मानीय मुख्य न्यायाधीश ने अपने भाषण में कहा था कि Trial Judges Play Safe by Not Granting Bail मानीय मुख्य न्यायाधीश दी वाई चैट्सड ने कहा कि धोर-धोर सर्वोच्चिक मूर्यों का तथा व्यक्तिकी स्वतंत्रता (Liberty) का मूल्यांकन घटाता जा रहा है। सुधार कोटे में 5 सालों में केसकी की Pendency 35% बढ़ रही है। 62 लाख केसों से बढ़कर 46.8 लाख हो गये हैं। हाई कोर्ट्स में 2019 से 2023 तक यह Pendingency 4.6 लाख से 62 लाख तक है। नीचे की अदालतों में यह Pendingency 4.4 कोड है। कानून मंत्री में सोबत ने ये अदालतों से अंदर आया है। इसका अर्थ है कि न्यायालय के द्वायल कोटे की तरीकी से अपाराधी को प्रतास किया जाए। इसी विनेश फॉरम ने उसी दिन क्वार्टर्ट फॉरम एवं सेमीफाइनल में एक घरी में कोई अपाराधी घर ही 7 PM को आया। सुधार का प्राप्त करने की प्रतीक्षा में यहीं जाए। जो Presumption को Discharge करने के प्रसन ही

पैदा होता है। केस में दो बजे शाम को साथ-साथ थे। न्यायाधीश न्यायालयों के पास समय नहीं है। जस्टिस ऑक्ने के निस्तारण में समय बर्बाद हो जाता है।

दिनांक 29 जुलाई 2024 के समाचार पर The Times of India के प्रथम पृष्ठ पर समाचार पढ़ा। यह समाचार द्वायल कोटे द्वारा जमानत देने के सम्बन्ध में या मानीय मुख्य न्यायाधीश ने अपने भाषण में कहा था कि Trial Judges Play Safe by Not Granting Bail मानीय मुख्य न्यायाधीश दी वाई चैट्सड ने कहा कि धोर-धोर सर्वोच्चिक मूर्यों का तथा व्यक्तिकी स्वतंत्रता (Liberty) का मूल्यांकन घटाता जा रहा है। सुधार कोटे में 5 सालों में केसकी की Pendency 35% बढ़ रही है। 62 लाख केसों



भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में स्पेन को हराकर भारत के लिए चौथा ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कदान हरमनपीत सिंह की अपार्ड में दोनों ओलंपिक 2020 के प्रदर्शन को दोहराया है। भारतीय टीम ने बेहरीन खेल का प्रदर्शन करते हुये स्पेन को 2-1 से हराकर इतिहास रचा है। पहले क्वार्टर के दौरान भारत ने नौ बार आक्रमक तरीके से स्पेन के सर्कत में प्रवेश किया लेकिन गोल करने में सफल नहीं हुये। इसके बाद स्पेन ने दूसरे क्वार्टर में फिर से आक्रमक शुरुआत करते हुए केवल तीन मिनट बाद मिले फैटल स्ट्रोक का कायदा जीते हुए 18वें मिनट में गोल दागकर अपनी टीम को बढ़त दिला दी। दूसरे क्वार्टर में भारतीय कदान हरमनपीत ने फैटल स्ट्रोक का गोल बनाया और 1-1 से बढ़त दिला दी। तीसरे क्वार्टर में 33वें मिनट में गोल दाग कर भारतीय टीम को 2-1 से बढ़त दिला दी और भारत ने अंत तक इस बढ़त को कायदा रखकर यह मुकाबला जीत लिया। पेरिस 2024 ग्रीष्मकालीन खेलों में यह भारत का लोक्यांतर कास्ट पक्क है और पुरुष हॉकी में यह 13वां ओलंपिक पक्क है। यूरोपियन 1972 के बाद यह पहली बार है जब भारत ने लगातार दो ओलंपिक पक्क जीते हैं। ओलंपिक में मिली इस जीत के साथ ही भारतीय गोलकीपर पी.आर. श्रीजश ने संन्यास ले लिया। भारतीय हॉकी टीम ने एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में स्वर्ण, लॉस एंजिलिस 1932 में स्वर्ण, बर्लिन 1936 में स्वर्ण, लंदन 1948 में स्वर्ण, हॉलिस्को 1952 में स्वर्ण, मैलबन 1956 में स्वर्ण, राम 1960 में रजत, टोक्यो 1964 में स्वर्ण, मैकेस्को सिटी 1968 में कास्ट, यूरोपियन 1972 में कास्ट, मॉस्को 1980 में स्वर्ण, टोक्यो 2020 में कास्ट और पेरिस 2024 में कास्ट जीता है।

चंद्रबाबू नायदू के अमित शाह को किये गये फोन के बाद, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक संसद में पेश होने से रुका

शायद पहली बार भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार किसी विधेयक को पेश करने का मन बना लेने के बाद पीछे हटी है

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 अगस्त सरकार में एक अत्याधिकारी भौमिका के अनुसार, केन्द्र सरकार ने "वक्फ बोर्ड में बैठक" के अंतर्गत, एक संयुक्त संसदीय कमेटी को संघें प्रदिया जाएगी। जातव्य है कि विषयक ने प्रस्तावित संशोधनों का कड़ा विवेदण किया था तथा एन.डी.ए. ग्राम्य विकास विभाग के घटक दल तेलुगुदेशम पार्टी (एन.डी.पी.) ने इन पर आपत्ति जताई थी।

तेलुगुदेशम पार्टी संसद बालयोगी ने कहा कि उनकी पार्टी सदन के परले पर विधेयक को अपने "संतर्त समर्थन" दे रही है। नायदू ने प्रस्तावित संशोधनों का कड़ा विवेदण किया था तथा एन.डी.ए. ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी अमित शाह के बीच देलीफॉन पर वार्ता दी गई है। इसे एक दुर्लभ अवसर ही कहा जायगा, जब भाजपा के नेतृत्व वाली एन.डी.ए.

- प्रस्तावित विधेयक में एक प्रमुख बात यह है कि वक्फ बोर्ड के अधिकारी पर कुछ अंकुश लगाते हुए, जिलाधीश को अधिकार दिये हैं, नियम कायदे बनाने के।
- साथ ही कुछ गैर मुस्लिम व्यक्तियों को और महिलाओं को वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाने का भी प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। कांग्रेस के सांसद वेणुगोपाल ने गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड की गवर्निंग समिति का सदस्य बनाने का विरोध किया और कहा, "जब राम मंदिर के निर्माण के लिए समिति का गठन किया गया था, तो क्या गैर हिन्दुओं को उस समिति का सदस्य बनाया गया था?"
- अखिलेश यादव ने इस संदर्भ में कहा, भाजपा को लोकसभा चुनाव में भारी झटका लगा था, अतः अब वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लाकर भाजपा, अपने कट्टरपंथी (हार्ड लाइनर) खेमों को खुश करना चाहती है।
- विषयक ने नेताओं ने यह भी कहा कि सरकार को कोई अधिकार नहीं है, वक्फ बोर्ड के काम में हस्तक्षेप करने का और वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करने का।

सरकार ने अपने किसी विधेयक पर उद्देश्य राज्य वक्फ बोर्ड के अधिकारों के कटौती करना तथा जिला मार्जिस्टों से संगठित प्रहार करते हुए, इसे वक्फ अधिनियम, 1995 में 44 संशोधन प्रस्तावित करने के बाद यह आइए। इसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड की गवर्निंग समिति एवं मुस्लिम-विवेदणी" के बाद यह आइए। इसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड की गवर्निंग समिति एवं मुस्लिमों को शामिल किया जाना भी प्रस्तावित किया गया था। अन्य विधेयकों के अंतर्गत विवेदणों का अंतिम पृष्ठ पर

विषयकी सदस्यों ने इस विधेयक पर में कटौती करना तथा जिला मार्जिस्टों को जिम्मेदारी देना किया जाए। इसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड की गवर्निंग समिति एवं मुस्लिम-विवेदणी" के बाद यह आइए। इसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड की गवर्निंग समिति एवं मुस्लिमों को शामिल किया जाना भी प्रस्तावित किया गया था। अन्य विधेयकों के अंतर्गत विवेदणों का अंतिम पृष्ठ पर

विषयकी सदस्यों ने इस विधेयक पर में कटौती करना तथा जिला मार्जिस्टों को जिम्मेदारी देना किया जाए। इसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड की गवर्निंग समिति एवं मुस्लिम-विवेदणी" के बाद यह आइए। इसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड की गवर्निंग समिति एवं मुस्लिमों को शामिल किया जाना भी प्रस्तावित किया गया था। अन्य विधेयकों के अंतर्गत विवेदणों का अंतिम पृष्ठ पर

विषयकी सदस्यों ने इस विधेयक पर में कटौती करना तथा जिला मार्जिस्टों को जिम्मेदारी देना किया जाए। इसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड की गवर्निंग समिति एवं मुस्लिम-विवेदणी" के बाद यह आइए। इसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड की गवर्निंग समिति एवं मुस्लिमों को शामिल किया जाना भी प्रस्तावित किया गया था। अन्य विधेयकों के अंतर्गत विवेदणों का अंतिम पृष्ठ पर

विषयकी सदस्यों ने इस विधेयक पर में कटौती करना तथा जिला मार्जिस्टों को जिम्मेदारी देना किया जाए। इसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड की गवर्निंग समिति एवं मुस्लिम-विवेदणी" के बाद यह आइए। इसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड की गवर्निंग समिति एवं मुस्लिमों को शामिल किया जाना भी प्रस्तावित किया गया था। अन्य विधेयकों के अंतर्गत विवेदणों का अंतिम पृष्ठ पर

विषयकी सदस्यों ने इस विधेयक पर में कटौती करना तथा जिला मार्जिस्टों को जिम्मेदारी देना किया जाए। इसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड की गवर्निंग समिति एवं मुस्लिम-विवेदणी" के बाद यह आइए। इसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड की गवर्निंग समिति एवं मुस्लिमों को शामिल किया जाना भी प्रस्तावित किया गया था। अन्य विधेयकों के अंतर्गत विवेदणों का अंतिम पृष्ठ पर

विषयकी सदस्यों ने इस विधेयक पर में कटौती करना तथा जिला मार्जिस्टों को जिम्मेदारी देना किया जाए। इसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड की गवर्निंग समिति एवं मुस्लिम-विवेदणी" के बाद यह आइए। इसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड की गवर्निंग समिति एवं मुस्लिमों को शामिल किया जाना भी प्रस्तावित किया गया था। अन्य विधेयकों के अंतर्गत विवेदणों का अंतिम पृष्ठ पर

विषयकी सदस्यों ने इस विधेयक पर में कटौती करना तथा जिला मार्जिस्टों को जिम्मेदारी देना किया जाए। इसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड की गवर्निंग समिति एवं मुस्लिम-विवेदणी" के बाद यह आइए। इसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड की गवर्निंग समिति एवं मुस्लिमों को शामिल किया जाना भी प्रस्तावित किया गया था। अन्य विधेयकों के अंतर्गत विवेदणों का अंतिम पृष्ठ पर

विषयकी सदस्यों ने इस विधेयक पर में कटौती करना तथा जिला मार्जिस्टों को जिम्मेदारी देना किया जाए। इसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड की गवर्निंग समिति एवं मुस्लिम-विवेदणी" के बाद यह आइए। इसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड की गवर्निंग समिति एवं मुस्लिमों को शामिल किया जाना भी प्रस्तावित किया गया था। अन्य विधेयकों के अंतर्गत विवेदणों का अंतिम पृष्ठ पर

विषयकी सदस्यों ने इस विधेयक पर में कटौती करना तथा जिला मार्जिस्टों को जिम्मेदारी देना किया जाए। इसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड की गवर्निंग समिति एवं मुस्लिम-विवेदणी" के बाद यह आइए। इसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड की गवर्निंग समिति एवं मुस्लिमों को शामिल किया जाना भी प्रस्तावित किया गया था। अन्य विधेयकों के अंतर्गत विवेदणों का अंतिम पृष्ठ पर

विषयकी सदस्यों ने इस विधेयक पर में कटौती करना तथा जिला मार्जिस्टों को जिम्मेदारी देना किया जाए। इसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड की गवर्निंग समिति एवं मुस्लिम-विवेदणी" के बाद यह आइए। इसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड की गवर्निंग समिति एवं मुस्लिमों को शामिल किया जाना भी प्रस्तावित किया गया था। अन्य विधेयकों के अंतर्गत विवेदणों का अंतिम पृष्ठ पर

विषयकी सदस्यों ने इस विधेयक पर में कटौती करना तथा जिला मार्जिस्टों को जिम्मेदारी देना किया जाए। इसके अंतर्गत

